

प्रतिलिपि आदेशा दिनांक 1-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिखरे सदस्य
राज स्व मण्डल मण्डल ग्वालियर प्रकरणक्रमांक निगा01233-तीन/14 विरुद्ध
आदेशा दिनांक 7-8-2000 पारित द्वारा अर कलेक्टर जिला उत्तरपुर प्रकरण
क्रमांक 289/स्व निगा0/अ-19/99-2000.

स्वामी श्री मती तुलसादेवा के वैधा वारिसान
अनन्तराम चौबे पुत्र स्व० श्री भावानरास चौबे
निवासी सटई रोड उत्तरपुर

--- आवेदक

विरुद्ध

मण्डल शासन

-- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1233/III/2014

जिला छतरपुर

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

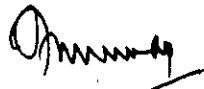
पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

1-5-2014

यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 290/अ-19/99-2000 स्व.प्रे.नि. में पारित आदेश दिनांक 7-8-2000 के विरुद्ध अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन सहित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम सूरजपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 120/4 रकबा 4.90 एकड़ पट्टा 1980 में मिला था तभी से वह भूमिस्वामी है किन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर ने भूमि बन विभाग के स्वामित्व पर दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश दिये है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 7-8-2000 के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम सूरजपुरा तहसील छतरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 120/4 ग रकबा 4-90 एकड़ जो बन विभाग के अधिसूचित क्षेत्र में है, आवेदक के अनुसार उसे तहसील न्यायालय से 1980 में पट्टा मिला है। तहसीलदार छतरपुर ने प्रतिवेदन क्रमांक 342/बी-121 / 99-2000 दिनांक 22-7-2000



प्रस्तुत कर उक्तांकित भूमि बन विभाग के सँसूचित क्षेत्र में होकर बन क्षेत्र की होना बताया है, जिस पर अपर कलेक्टर, छतरपुर ने आदेश दिनांक 7-8-2000 से तहसीलदार के प्रतिवेदन को सही होना मानकर बन भूमि दर्ज करने के आदेश दिये हैं। वैसे भी बन विभाग की भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं की जा सकती।

4/ उपरोक्त कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 290/अ-19/99-2000 स्व.प्रे.नि. में लिया गया निर्णय दिनांक 7-8-2000 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।


सदस्य